

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-88/2017

महिपालसिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना
जिला झुन्झुनूँ राज०

---अपीलान्ट---

---बनाम---

- 1- सरिथादेवी पत्नी सुलतानसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील
- 2- सुमेरसिंह पुत्र सुलतानसिंह बुहाना जिला झुन्झुनूँ राज०
- 3- पवनकुमार पुत्र सुलतानसिंह
- 4- पार्वती पुत्री सुलतानसिंह पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनूँ हाल आबाद बापडोली तहसील नारनोल जिला
महेन्द्रगढ
- 5- सन्तरा पुत्री सुलतानसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी खानपुर
हाल आबाद देवलावा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूँ राज०
- 6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना ।
- 7- उप पंजीयक बुहाना ।

---रेस्पोंडेन्ट्स---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली
दिनांक 15-5-2017 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
बुहाना ।

---0---

उपस्थिति-

- 1- श्रीमति पूनम डूडी एडवोकेट- अपीलान्ट
- 2- श्री राजेन्द्र बुडानिया एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 15.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेशा कर निवेदन किया कि ग्राम खानपुर में आराजी जमाबन्दी सं०- 2069 से 2072 के खाता संख्या-140 खसरा नं० 19 रकबा 1.52 हैक्टर, ख०नं० 20 रकबा 0.82 हैक्टर, ख०नं० 21 रकबा 0.03 हैक्टर, ख०नं० 22 रकबा 4.76 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 6.38 हैक्टर में वादी रेकार्डेड खातेदार काबतकार है। जिस में वादी का 1/6 व प्रतिवादी सं०-1 से 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। किन्तु प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काबत में दखल अन्दाजी करते हैं। उन्हें खाता विभाजन कहा तो उन्होंने मना कर दिया। जिस पर वादी ने यह दावा पेशा किया जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर दावा डिक्री कर दिया जिससे भ्रुब्ध होकर वादी/से अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने दिनांक 21-10-2016 को दावे में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के आदेश दिए जिस पर तहसीलदार बुहाना ने कुरेजात तैयार किये जो सही न बनाकर अपीलान्ट का जिस भूमि पर कब्जा था उस पर कब्जा न दिखा कर विभाजन प्रस्ताव में गलत दी है। जिस पर अपीलान्ट ने आपत्ति पेशा की किन्तु अदालत मातहत ने आपत्ति पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-5-17 को निरस्त कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से पुनः अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार कर मंगावाये जाने के आदेश दिए जावे। प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभावकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तैयार किये है जो मौके के विपरित तैयार कर भिजवाये है । अपीलान्ट अपने 1/6 हिस्से पर मौके पर काबिज है उसके विपरित मौके पर हिस्सा दिया है । जिसकी मैंने आपत्ति की जिसे अदालत मातहत ने बिना किये आदेश पारित कर विधि के विपरित निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण अदालत मातहत का रिमाण्ड किया जावे जिसमें अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि वह मौके पर अपीलान्ट की मौजूदगी में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाकर अपना निर्णय पुनः पारित करे ।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । तहसीलदार ने मौके पर मौके के अनुसार पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है । उन पर आपत्ति लेकर आपत्ति का निस्तारण करने के बाद अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाप्त की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं०- 2069 से 2072 में विवादित आराजी की खातेदारी सुलतान पुत्र सुखराम के नाम दर्ज है । खातेदार सुलतान के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर नामान्तरकरण सं०302 दिनांक 22-9-2014 से सुलतान के बजाय सरिया देवी पत्नी सुलतान, महीपालसिंह, सुमेरसिंह, पवनकुमार पि० सुलतान, पर्वती, सन्तरा पुत्रीयां सुलतान के नाम दर्ज हुई । मुताबिक जमाबन्दी उक्त आराजी में अपीलान्ट का तथा रेस्पोंडेंट सं०-1 से 5 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्स हुआ । तहसीलदार ने मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार

कर भिजवाये । विभाजन प्रस्ताव के आधार पर मजमें आम में सरपंच ग्राम पंचायत की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित किया है । जिस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अदालत मातहत का निर्णय विधि संगत है ।

अपील अमीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुढाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-5-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.11.2017 को सुनाया गया ।



॥ भवरलाल मेहरडा ॥

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर